खबरों में रहे स्टॉक

सुंदरम-क्लेटन — निदेशक मंडल ने तरजीह निर्गम के जरिये 400 करोड़ रुपये जुटाने को दी मंजूरी
₹ 1,539.5 पिछला बंद भाव
₹ 1,665.2 आज का बंद भाव
8.2 % ▲

एबीबी इंडिया — प्रीमियम पेंट के विकल्प प्रदान करने के लिए महिंद्रा ऐंड महिंद्रा से ठेका मिला
₹ 8,514.5 पिछला बंद भाव
₹ 8,614.9 आज का बंद भाव
1.2 % ▲

फेडरल बैंक — सकल ऋण पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़कर 2,24,139 करोड़ रुपये हुआ
₹ 175.1 पिछला बंद भाव
₹ 181.4 आज का बंद भाव
3.6 % ▲

पर्सिस्टेंट सिस्टम्स — अमेरिका की स्टारफिश एसोसिएट्स एलएलसी का अधिग्रहण करने का इरादा
₹ 4,498.9 पिछला बंद भाव
₹ 4,595.9 आज का बंद भाव
2.2 % ▲

केईसी इंटरनैशनल — टीऐंडडी और अक्षय ऊर्जा कारोबारों में 1,017 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले
₹ 902.7 पिछला बंद भाव
₹ 921.2 आज का बंद भाव
2.0 % ▲

संक्षेप में

एक्मे सोलर ने आईपीओ के दस्तावेज जमा कराए

नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एक्मे सोलर होल्डिंग्स लि. ने आईपीओ के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। सेबी के पास दाखिल आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार, गुरुग्राम स्थित कंपनी के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में 2,000 करोड़ रुपये के नए शेयरों की पेशकश होगी। इसमें एक्मे क्लीनटेक सॉल्युशंस द्वारा 1,000 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) भी है। इस प्रस्ताव में पात्र कर्मचारियों के लिए आरक्षण भी है। कंपनी 'आईपीओ-पूर्व नियोजन' के रूप में 400 करोड़ रुपये तक की प्रतिभूतियां जारी करने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा हो जाता है, तो नए निर्गम का आकार कम हो जाएगा। कंपनी का इरादा नए निर्गम से प्राप्त 1,500 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर्ज के भुगतान में करने का है। इसके अलावा एक हिस्सा सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। *भाषा*

लोहम बैटरी उत्पादन में लगाएगी 1,000 करोड़ रु

लीथियम-आयन बैटरी पैक विनिर्माता तथा पुनर्चक्रण कंपनी लोहम ने मैंगनीज आधारित लीथियम-आयन बैटरी विकसित करने तथा उसका विनिर्माण करने के लिए अगले तीन साल में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की बुधवार को घोषणा की। इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि उसने नई परियोजना में मदद के लिए टेस्ला के अनुभवी चैतन्य शर्मा को अपने साथ लिया है। *भाषा*

एआई के लिए डीपीआई की तर्ज पर चलेंगे : वैष्णव

आशुतोष मिश्रा
नई दिल्ली, 3 जुलाई

डिजिटल सार्वजनिक ढांचे (डीपीआई) के निर्माण के लिए भारत के अनूठे दृष्टिकोण पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि देश आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के संबंध में इसी तरह का मॉडल अपनाने जा रहा है।

वैष्णव ने ग्लोबल इंडिया एआई समिट को संबोधित करते हुए कहा कि डीपीआई की ही तरह सरकार एआई के लिए भी एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनाएगी, जहां सभी संबंधित संसाधन और जानकारी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

वैष्णव ने कार्यक्रम में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा 'सरकार एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में निवेश करेगी, जहां कंप्यूट पावर, उचच गुणवत्ता वाले डेटा सेट, प्रोटोकॉल का सामान्य सेट, फ्रेमवर्क का सामान्य सेट, तकनीकी और साथ ही कानूनी ढांचे जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे। फिर स्टार्टअप, उद्यमी, शिक्षाविद और वे लोग जो कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ऐप्लिकेशनों पर काम कर रहे हैं, अपने प्रयासों को तेज करने के लिए इस साझा प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।'

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कुछ महीने पहले घोषित 10,000 करोड़ रुपये वाले इंडिया एआई मिशन की आधारशिला रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले दो से तीन महीने में यह मिशन शुरू हो जाएगा। एआई के प्रति देश की सोच के संबंध में बात करते हुए वैष्णव ने कहा 'हम अच्छा डेटा सेट, उच्च गुणवत्ता वाला डेटा सेट हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो शोधकर्ताओं, स्टार्टअप के प्रयासों में और अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं। हमारे पास ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट कार्यक्रम होगा, जहां हमारी सामाजिक समस्याओं, हमारी आर्थिक समस्याओं के लिए प्रासंगिक ऐप्लिकेशन विकसित की जा सकती हों, उन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और कौशल विकास पर भी बहुत जोर दिया जाएगा।'

मंत्री ने एआई से उत्पन्न होने वाले मसलों पर भी चिंता जताई की और कहा कि पूरी दुनिया प्रौद्योगिकी के मामले में इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा 'विकासशील और आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश आज सार्वभौमिक समर्थन, सार्वभौमिक विचार प्रक्रिया और कम से कम कुछ सामान्य बुनियादी सिद्धांतों की तलाश कर रहे हैं, जिन पर दुनिया को एक तरफ संभावनाओं और दूसरी तरफ चुनौतियों का जवाब देना है।'

'राजनीतिक आम सहमति जरूरी'

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी के कारण होने वाले संभावित जोखिमों को रोकने के लिए पहले से आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) विनियमन पर चर्चा कर रही है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट से इतर संवाददाताओं से बातचीत में वैष्णव ने कहा, 'एआई विनियमन पर चर्चा की जा रही है। इसके लिए राजनीतिक आम सहमति की भी जरूरत होगी।'

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भले ही एआई कई समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा उपकरण हो सकता है, लेकिन उससे होने वाले जोखिमों को भी नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'हम यह भी मानते हैं कि समाधान दुनिया भर के देशों से बातचीत के जरिये आना चाहिए। यह अकेले किसी देश द्वारा नहीं किया जा सकता है।'

ऐप डेवलपमेंट पहल का समर्थन करेगी ओपन एआई

आशुतोष मिश्रा
नई दिल्ली, 3 जुलाई

चैटजीपीटी की मूल कंपनी ओपन एआई ने इंडिया एआई मिशन के तहत ऐप डेवलपमेंट पहल में भागीदारी के जरिये इस कार्यक्रम को अपना समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।

इंडिया एआई मिशन के तहत मिलेगी मदद

ओपन एआई के उपाध्यक्ष श्रीनिवास नारायणन ने कहा 'इंडिया एआई मिशन की ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट पहल का समर्थन करने के लिए ओपन एआई प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय डेवलपर हमारे मॉडल पर निर्माण कर सकें और बड़े स्तर पर सामाजिक लाभ पहुंचा सकें तथा हम वाकई मंत्रालय के साथ बातचीत जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं और यह आकलन कर रहे हैं कि हम सबसे अधिक मूल्य कहां जोड़ सकते हैं।'

इंडिया एआई मिशन के सात स्तंभों में से एक के रूप में चिह्नित इस ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट पहल का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों के विभागों और अन्य संस्थानों की समस्या की रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है।

दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट को संबोधित करते हुए नारायणन ने कहा कि कंपनी बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लेते समय भारत को ध्यान में रख रही है। भारत में एआई के विकास के संबंध में बात करते हुए नारायणन ने कहा कि इस तकनीक ने भारत में पहले से ही गतिशील उद्यमी तंत्र की रफ्तार और गतिशीलता को बढ़ाया है।

उन्होंने कहा 'उद्यमी बाजार के अंतर को समझते हैं। वे नवाचार वाले उत्पादों को विकसित कर रहे हैं और चैटजीपीटी जैसे टूल पूरी तरह नए ढंगों से इसे बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। हम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की लागत कम कर रहे हैं। हम डेवलपरों को कोड लिखने में सक्षम कर रहे हैं और हम कंप्यूटिंग के लिए पूरी तरह से संवादात्मक और प्राकृतिक इंटरफेस सृजित करने में उनकी मदद कर रहे हैं।'

एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
SJVN Green Energy Limited
(A Wholly Owned Subsidiary of SJVN Limited)
CIN: U40100HP2022GOI009237
एसजेवीएन ग्रीन SJVN GREEN

ई–निविदा सं.: SGEL/CHQ/Contracts/BoS-MH/SPP/2024

SGEL के द्वारा ''महाराष्ट्र में चार विभिन्न स्थानों पर कुल 400 मेगावाट (AC) (एमएसईडीसीएल फेज VII एवं IX) के चार सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बैलेंस ऑफ सिस्टम पैकेज, पावर की निकासी एवं तीन (03) वर्ष के व्यापक परिचालन और रखरखाव'' के लिए निविदा दस्तावेज में कुछ संशोधन किए गए हैं। विस्तृत विवरणों के लिए वेबसाइट https://www.bharat-electronictender.com, www.eprocure.gov.in एवं www.sjvn.nic.in को देखें। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 18.07.2024 (14:00 बजे) है।
संशोधन यदि कोई हो, केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर जारी किए जाएंगे।

उप महाप्रबंधक (संविदा)
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
कॉर्पोरेट मुख्यालय, शक्ति सदन, शानन, शिमला (हि.प्र.)
ई–मेलः contracts.sgel@sjvn.nic.in

IndoStar Home Finance Private Limited
INDOSTAR
Regd. Office: - Unit No. 305, 3rd Floor, Wing 2/E, Corporate Avenue, Andheri- Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400093
CIN : U65990MH2016PTC271587 Tel: +91 22 45107701
Email: connect@indostarhfc.com; Website: www.indostarhfc.com

सूचना

एतद्द्वारा मास्टर निर्देश– अ–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशवली, 2021 के अनुच्छेद 93 के अनुसार सूचित किया जाता है कि **इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वितीय तल, बी–15, परी प्लाजा, राधिका विहार फेज–2 मोती मंजिल के पास, मथुरा–281004 पिन कोड–281004** पर अवस्थित कंपनी का शाखा कार्यालय **09 अक्टूबर, 2024** को व्यावसायिक समय समाप्त होने से बंद रहेगा। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो आप ऊपर वर्णितानुसार निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या **connect@indostarhfc.com** पर एक ईमेल भेज सकते हैं।
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट (**www.indostarhfc.com**) पर देखी जा सकती है।

कृते इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
निधि सदानी
कंपनी सचिव
दिनांक : 03–07–2024

एडेलवेइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
Edelweiss Asset Reconstruction
CIN:- U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेंट्रल एवं कार्यालयः- एडेलवेइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कालिना, मुम्बई-400098

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित (नियम 3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत मांग सूचना दिनांकित **15-12-2023** जारी की थी, जिसमें **1. मैसर्स फ्रोबेल कॉनवेंट मोनटेसरी स्कूल,** इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, बदियां मलिहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226104, **2. मैसर्स बाबा हरीवंश एजुकेशन सोसाइटी,** इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, बदियां मलिहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226104, **3. श्री पद्माकर सिंह पिता दयाराम, ग्राम माझी,** निखरोजपुर, रघुनाथपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226104, दूरभाष सं. 9415129089, **4. श्रीमती सुनैना देवी पति ऋषि यादव,** ग्राम माझी, निखरोजपुर, रघुनाथपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226104, दूरभाष सं. 7905274620, **ऋण खाता सं. S18LUC-LUC-002623, U22LUC-LUC-019569, U21LUC-LUC017873, U21LUC-LUC-016358 तथा U20LUC-LUC-014585** को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम **रु. 20,07,736/- (रुपये बीस लाख सात हजार सात सौ छत्तीस मात्र)** चुकता करने को कहा गया था।
चूंकि मैसर्स वर्थना फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां बाद में 'वीएफपीएल' कहा गया है) ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत **समनुदेशन करार दिनांकित 28 मार्च 2024 के मार्फत** एडेलवेइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, **ईएआरसी ट्रस्ट एससी-467 (जिसे यहां बाद में "ईएआरसी" कहा गया है)** के टस्ट्री के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत है को वित्तीय सम्पत्तियां सुपुर्द कर दी है। **ईएआरसी** ने **वीएफपीएल** की स्थान ग्रहण किया है एवं वित्तीय सम्पत्ति के संबंध में **वीएफपीएल** के सभी अधिकारों, स्वत्वाधिकार एवं हितों के साथ कर्जदार द्वारा हासिल वित्तीय सहायता के संबंध में अंतर्निहित प्रतिभूति ब्याज, गारंटी, गिरवी को **ईएआरसी** को निहित कर दिया है तथा **ईएआरसी** प्रत्याभूत ऋणदाता के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर रही है।
कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण एतद्द्वारा कर्जदारों तथा जन साधारण को सूचित किया जाता है कि एडेलवेइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत **01 जुलाई, 2024** को यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।
प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
विशेष कर कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति के संबंध में कोई भी सौदा **ऋण खाता सं. S18LUC-LUC-002623, U22LUC-LUC-019569, U21LUC-LUC017873, U21LUC-LUC-016358 तथा U20LUC-LUC-014585 के तहत रु. 20,07,736/- (रुपये बीस लाख सात हजार सात सौ छत्तीस मात्र)** तथा उस पर ब्याज की रकम के लिए एडेलवेइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रत्याभूत सम्पत्तियों का विवरण
सम्पत्ति की अनुसूची
अनुसूची एः ग्रामः बदैइया, परगना तहसील-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ में स्थित खसरा नं. 309 एवं 311 मिन, क्षेत्रफल 0.0942 हेक्टर रूपी सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, चौहद्दी निम्नानुसारः खसरा नं. 311. **पूर्वः** श्री बच्चू सिंह एवं अन्य की भूमि, **पश्चिमः** श्री गया प्रसाद की भूमि, **उत्तरः** श्री राम लखन सिंह की भूमि, **दक्षिणः** बदैयां सम्पर्क मार्ग।
अनुसूची बीः ग्रामः बदैइया, परगना तहसील-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ में स्थित खसरा नं. 309 एवं 311 मिन की भूमि पर निर्मित भवन रूपी सम्पत्ति, क्षेत्रफल 429 मीटर, का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, चौहद्दी निम्नानुसारः खसरा नं. 309. **पूर्वः** श्री बच्चू सिंह एवं अन्य की भूमि, **पश्चिमः** दाता की भूमि, **उत्तरः** श्री राम लखन की भूमि, **दक्षिणः** बदैयां सम्पर्क मार्ग।

स्थान : लखनऊ
तारीखः 04.07.2024
अधिकृत अधिकारी
कृते एडेलवेइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सौदा नहीं पटा और बंद हो गया 'कू'

आर्यमन गुप्ता
नई दिल्ली, 3 जुलाई

वित्तीय समस्याओं से जूझ रही कंपनी के कर्मियों की संख्या तेजी से घटी है

एक समय सोशल मीडिया दिग्गज एक्स (पूर्व में ट्विटर) की भारतीय प्रतिस्पर्धी के तौर पर चर्चित रहे माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी के संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण ने बुधवार को लिंक्डइन पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

राधाकृष्ण ने कहा, 'हमारी ओर से यह अंतिम अपडेट है। हमारी साझेदारी की बातचीत विफल हो गई है और हम जनता के लिए अपनी सेवा बंद कर रहे हैं। हमने कई बड़ी इंटरनेट कंपनियों, समूहों और मीडिया घरानों के साथ साझेदारी की संभावना तलाशी, लेकिन इन वार्ताओं से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।' उन्होंने कहा कि ज्यादातर इच्छुक पक्ष उपयोगकर्ता द्वारा तैयार कंटेंट से संतुष्ट नहीं थे। उनमें से कुछ ने सौदे के आखिर में अपना फैसला बदल लिया।

अपुष्ट खबरों से पता चला है कि डेलीहंट ओर शेयरचैट की मालिक वेरसे इनोवेशन भी कू को खरीदने के लिए बातचीत कर रही थी।

राधाकृष्ण ने कहा, 'हालांकि हम ऐप को चालू रखना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया ऐप को चालू रखने के लिए प्रौद्योगिकी सेवाओं की लागत बहुत अधिक है और इस वजह से हमें यह कठिन निर्णय लेना पड़ा है।' मार्केट इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के आंकड़े से पता चलता है कि वर्ष 2022 में 5,868 स्टार्टअप ने विपरीत वृहद आर्थिक हालात की वजह से अपना परिचालन बंद किया था। हालांकि 2023 में यह आंकड़ा घटकर 1,720 रह गया और 2024 में अब तक महज 4 स्टार्टअप ने अपना परिचालन बंद किया है, क्योंकि हालात में सुधार आया है।

पिछले कुछ वर्षों में बंद हो चुके कुछ स्टार्टअप में निकी, जिपगो, क्रेजो डॉट फन, फ्रंटरो और ग्रामफैक्ट्री आदि शामिल हैं।

मजबूत शुरुआत

वर्ष 2020 में स्थापित कू एक ऐसा बहुभाषी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बातचीत करने की अनुमति देता था। इसने प्रभावशाली लोगों को नेटवर्क बनाने और अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत करने की भी अनुमति दी।

बेंगलूरु की इस फर्म को 2020 में अनुचित कंटेंट मॉडरेशन की वजह से एक्स और भारत सरकार के बीच टकराव का लाभ मिला। कई सेलेब्रिटी, सरकारी अधिकारी और नागरिक एक्स से हटकर इसके स्वदेशी रूप निर्मित विकल्प की ओर आकर्षित होने लगे। लॉन्च होने के तीन साल बाद, इस स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर 6 करोड़ से अधिक ऐप डाउनलोड हुए।

चुनौतियां और वित्तीय संकट

अप्रैल में, कू ने घोषणा की कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान को इस महीने के लिए रोक रही है क्योंकि उसे वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे सबसे बड़े माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इसका स्थान मेटा के थ्रेड्स से भी पिछड़ गया, जिसने अपनी पेशकश के महज पांच दिनों के अंदर 10 करोड़ वैश्विक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बना ली।

जून से कंपनी के कर्मियों की संख्या 80 प्रतिशत तक घट गई है, इसमें वरिष्ठ स्तर पर कर्मचारियों का बाहर जाना भी शामिल है, जिसके कारण कंपनी में लगभग 50 कर्मचारी रह गए हैं। शेष कर्मियों को भी अक्टूबर 2023 से 40 प्रतिशत तक की वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है।

छूट के सहारे बिक्री बढ़ाने में जुटीं वाहन कंपनियां

पृष्ठ 1 का शेष

फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा, 'मॉनसून के मौसम में ज्यादा त्योहार नहीं होते हैं और मौसम का भरोसा नहीं होने के कारण वाहनों की खरीद पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में जुलाई में वाहनों पर ज्यादा छूट दी जा रही है ताकि बिक्री पर असर न पड़े।' सिंघानिया ने कहा कि कुछेक मॉडलों को छोड़ दें तो डीलरों के पास ज्यादातर मॉडलों का स्टॉक पड़ा हुआ है। एसयूवी की मांग बनी हुई है इसलिए उस पर कम छूट दी जा रही है मगर एंट्री श्रेणी की गाड़ियों और हैचबैक पर ज्यादा छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह छूट त्योहारी सीजन से पहले तक जारी रहेगी।

बिना बिके वाहनों के अंबार पर बात करते हुए सिंघानिया ने कहा कि मई में डीलरों के पास इतनी गाड़ियां थीं कि उन्हें बेचने में 55 से 60 दिन लग जाते। उम्मीद में स्टॉक घटकर केवल 30 दिन के बराबर रह जाएगा। उन्होंने थोक और रिटेल बिक्री में तालमेल बिठाने पर जोर दिया ताकि ज्यादा स्टॉक से डीलरों के मुनाफे पर चोट न पड़े।

मारुति बलेनो के मैनुअल पेट्रोल मॉडल पर 35,000 रुपये और ऑटोमैटिक पेट्रोल पर 40,000 रुपये की नकद छूट दे रही है। वह जिम्नी पर मॉडल और उपलब्धता के आधार पर मारुति सुजूकी सबस्क्राइब के जरिये जेटा मॉडल पर 1 लाख रुपये (बिना सबस्क्राइब योजना के) से लेकर अल्फा पर 2.50 लाख रुपये (सबस्क्राइब के साथ) तक की छूट दी रही है। इसी तरह एक्सएल6 के पेट्रोल मॉडल पर 20,000 रुपये और सीएनजी मॉडल पर 15,000 रुपये की नकद छूट दी जा रही है। पेट्रोल मॉडल पर 20,000 रुपये और सीएनजी पर 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा अपनी विभिन्न कारों पर नकद छूट और लाभ दे रही है। एक्सूयवी 400 इलेक्ट्रिक एसयूवी पर 4 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है, जिसमें 3.80 लाख रुपये नकद छूट है और ऐक्सेसरीज पर 20,000 रुपये की छूट दी जा रही है। स्कॉर्पियो-एन पर 60,000 से 1 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। एक्सयूवी700 एक्स5 पर 1.30 लाख से 1.50 लाख रुपये और एक्स 7 पर 1.50 लाख रुपये की छूट है। बोलेरो पर 69,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

इस बार गर्मी में छाए रहे क्षेत्रीय बेवरिज ब्रांड

शार्लीन डिसूजा
मुंबई, 3 जुलाई

इस गर्मी में न केवल प्रमुख बेवरिज ब्रांडों ने बल्कि छोटे ब्रांडों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कई क्षेत्रीय ब्रांड मौजूदा बाजार में अपनी पैठ और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में कामयाब रहे। कैंटर वर्ल्डपैनल ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि हालांकि गर्मियों के आंकड़े अभी पूरी तरह नहीं मिले हैं लेकिन एक तथ्य जो 'हमें साफ दिख रहा है, वह है कि इस गर्मी में शीतल पेय श्रेणी में क्षेत्रीय ब्रांड बेहतर ढंग से बढ़े हैं।'

कैंटर वर्ल्डपैनल के प्रबंध निदेशक (दक्षिण एशिया) के रामकृष्णन ने कहा, 'मार्च-मई 2023 में संयुक्त रूप से क्षेत्रीय ब्रांडों की पैठ 5 प्रतिशत थी। साल 2024 (मार्च-मई) में यह पैठ उछलकर 7 प्रतिशत हो गई। शहरी क्षेत्रों में यह उछाल 8 से 10 प्रतिशत हो गई है।

फूड डिलिवरी बाजार में होगी 18 प्रतिशत वृद्धि

बेन-स्विगी की रिपोर्ट में जताया गया अनुमान

ऑनलाइन फूड डिलिवरी बाजार साल 2030 तक 18 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़कर 2.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है और यह कुल खाद्य सेवा बाजार में 20 प्रतिशत का योगदान करेगा। एक हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

ऑनलाइन फूड डिलिवरी क्षेत्र पिछले कुछ साल के दौरान लगातार बढ़ रहा है। साल 2019 और साल 2023 के बीच इसकी पैठ आठ प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है, जो 2.8 गुना वृद्धि को दर्शाता है।

यह वृद्धि भारत के बड़े खाद्य सेवा बाजार से आगे है, जिसमें घर से बाहर भोजन करना और ऑर्डर पर खाना मंगाना शामिल है। बेन ऐंड कंपनी और स्विगी द्वारा किए गए अध्ययन 'हाउ इंडिया ईट्स' के अनुसार वर्तमान में खाद्य सेवा बाजार का मूल्य 5.5 लाख करोड़ रुपये है और अगले सात साल के दौरान इसमें सालाना 10 से 12 प्रतिशत की दर से इजाफा होने की उम्मीद है, जो साल 2030 तक नौ लाख करोड़ रुपये से लेकर 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि का यह पथ दमदार बुनियादी चीजों से प्रेरित होगा जिसमें ग्राहक आधार का विस्तार, बढ़ती खपत के अवसर और आपूर्ति वृद्धि शामिल है।

स्विगी के फूड मार्केटप्लेस के मुख्य कार्य अधिकारी रोहित कपूर ने कहा 'भारतीय खाद्य सेवा बाजार, खास तौर पर फूड डिलिवरी में पिछले कुछ साल के दौरान काफी तेजी से वृद्धि देखी गई है। *बीएस*

शेयर बेचने या गिरवी रखने पर फैसले के लिए बैजूस ने मांगा समय

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 3 जुलाई

नकदी किल्लत का सामना कर रही एडटेक फर्म बैजूस बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के सामने पेश हुई। कंपनी ने यह फैसला करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा है कि उसे निवेशकों के साथ विवाद के बीच अपनी संपत्ति को गिरवी रखने, बेचने अथवा हस्तांतरण नहीं करने का वचन देना चाहिए।

इस साल की शुरुआत में बैजूस के अमेरिकी ऋणदाताओं ने एडटेक कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए बेंगलूरु में एनसीएलटी पीठ का रुख किया था। बैजूस को 1.2 अरब डॉलर का टर्म लोन देने वाले ऋणदाताओं के तदर्थ समूह ने कहा कि जीएलएस ट्रस्ट लिमिटेड (टर्म लोन के प्रशासनिक और रेहन एजेंट) ने थिंक ऐंड लर्न के खिलाफ पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी। 29 मई को बैजूस के अमेरिकी ऋणदाताओं ने एनसीएलटी से अनुरोध किया था कि उसे अपने शेयरों को गिरवी रखने, बेचने अथवा हस्तांतरित करने से रोका जाए।

उम्मीद है कि अब बैजूस अपने फैसले के बारे में एनसीएलटी को जानकारी देगी और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को की जाएगी। अधिकरण ने 3 जुलाई को बैजूस दिवस के तौर पर बताया था क्योंकि उस दिन एडटेक कंपनी के खिलाफ करीब 10 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली थी।

एक दूसरे मामले में एनसीएलटी के बेंगलूरु पीठ ने टेलीमार्केटिंग कंपनी सर्फर और मोबाइल फोन विनिर्माता ओपो द्वारा बैजूस के खिलाफ दायर दिवालिया याचिका को सुरक्षित रख लिया है।

पिछले हफ्ते, ओपो ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के बेंगलूरु पीठ को बताया था बैजूस ने उसके फोन पर उनके ऐप्लिकेशन प्री-इंस्टॉल करने के लिए 13 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। ओपो ने कहा था कि बैजूस ने उसे बकाया रकम के भुगतान की बात स्वीकार की है और अब यह स्पष्ट हो गया है कि बकाया रकम वसूलने के लिए एडटेक कंपनी को दिवालिया घोषित करना होगा। सर्फर टेक्नोलॉजिज का तर्क था कि बैजूस पर 2.3 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था। कंपनी ने दावा किया कि उसने दिसंबर, 2023 में इस बारे में एडटेक कंपनी को नोटिस भी भेजा था।

लखनऊ संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, बी–5, अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र. से मुद्रित एवं बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेहरा बिज़नेस चैंबर्स, चैंबर नंबर–8,19–सी2एन विधान सभा मार्ग, लखनऊ – 226001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल आरएनआई नं. UPHIN/2008/25502 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन – 033–22101314/1022/1600
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं